भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1425
02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

वैश्विक इस्पात बाजार में देश की स्थिति मजबूत करने के लिए कदम

1425. श्री संत बलबीर सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चुनौतियों का सामना कर रहे वैश्विक इस्पात बाजार में देश की स्थिति मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) देश में इस्पात उत्पादन बढ़ाने और सुधारने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(क) इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। देश में इस्पात के उत्पादन और खपत में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआईएंडएसपी) का कार्यान्वयन।

ii. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात हेतु 29,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अनुमानित है।

iii. इस्पात मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.07.2024 को 16 प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशानिर्देश लॉन्च किए गए, जिनके परिणामस्वरूप प्रचालनों में सुरक्षित कार्य पद्धतियों को मानकीकृत करके इस्पात उद्योग को उत्पादकता वृद्धि में सहायता मिलेगी।

iv. घरेलू इस्पात उद्योग से संबंधित समस्याओं के समाधान तथा आयात की अधिक प्रभावी निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया और एसआईएमएस 2.0 को दिनांक 25.07.2024 को लॉन्च किया गया।

v. देश में इस्पात के उपयोग, इस्पात की समग्र मांग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता के साथ मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ।

जारी..... 2/-

vi. इस्पात विनिर्माण हेतु अधिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों व राज्यों के साथ समन्वय करना।

vii. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

viii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण एवं आयात को रोकने तथा आम जनता को बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 145 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।

भारत वर्ष 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बाद इस्पात उत्पादक बना गया और तब से उसी स्थान पर है।

(ग) इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिन्ट को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. इस्पात क्षेत्र के अकार्बनीकरण हेतु विभिन्न पद्धतियों पर चर्चा, विचार-विमर्श और सिफारिश करने के लिए उद्योग, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, एस एंड टी निकायों, विभिन्न मंत्रालयों तथा अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए 14 कार्यबलों का गठन किया गया है।

ii. इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 इस्पात निर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिए स्वदेशी रूप से उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है।

iii. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन तथा उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को अधिसूचित किया है। इस्पात क्षेत्र को भी इस मिशन में एक हितधारक बनाया गया है।

iv. मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम सितंबर, 2021, इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने की परिकल्पना करता है।

v. जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है।

vi. राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना इस्पात उद्योग को ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

vii. इस्पात क्षेत्र ने आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजनाओं में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध श्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकियों (बीएटी) को अपनाया है।

viii. ऊर्जा दक्षता सुधार हेतु जापान के नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) की मॉडल परियोजनाओं को इस्पात संयंत्रों में कार्यान्वित किया गया है।

******